

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2030

मद क्रमांक 1

पंजीयन विभाग कम्प्यूटराइजेशन अंतर्गत पंजीकृत पुराने अभिलेखों की बैकलॉग स्कैनिंग तथा डाटा एन्ट्री हेतु ₹1540.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,40,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 2

1. आबकारी विभाग अंतर्गत मुख्यालय के लिए फर्नीचर हेतु ₹5.00 लाख एवं कम्प्यूटर सह उपकरण हेतु ₹7.00 लाख कुल ₹12.00 लाख का व्यय संभावित है।

2. आबकारी विभाग आसवनी एवं बाटलिंग इकाइयों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु सीसीटीवी की स्थापना तथा होलोग्राम के ट्रैक एंड ट्रैस सिस्टम के लिए ₹500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,12,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

आबकारी विभाग में कम्प्यूटराइजेशन के क्रियान्वयन हेतु ₹19.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹19,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 4

आबकारी विभाग अंतर्गत जिला कार्यालयों के लिए फर्नीचर हेतु ₹20.00 लाख तथा कम्प्यूटर सह उपकरण क्रय हेतु ₹15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹35,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2040

मद क्रमांक 5

वाणिज्यिक कर विभाग में कम्प्यूटराइजेशन तथा जीएसटीएन के क्रियान्वयन हेतु ₹685.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹6,85,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 6

वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत विज्ञापन प्रचार मद में ₹60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹60,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 7

वाणिज्यिक कर विभाग के लिए 1 नवीन हल्का वाहन हेतु ₹15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 8

पंजीयन विभाग के लिए 1 नवीन हल्का वाहन हेतु ₹6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹6,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत विक्रय कर कार्यालय बिलासपुर के भवन निर्माण हेतु ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

पंजीयन विभाग अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालय धमतरी, सिमगा तथा कोरबा के भवन निर्माण हेतु ₹195.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,95,00,000 का प्रावधान किया गया है।